जर्मनी सारे परमाणु संयंत्र बंद करेगा

जर्मनी ने 30 मई को घोषणा कर दी कि वह 2022 तक अपने सारे परमाणु बिजली घर बंद कर देगा। इसका परिणाम यह होगा कि उसे अगले दशक में अपनी बिजली आपूर्ति के वैकल्पिक साधनों का विकास करना होगा।

जर्मनी में फिलहाल17 परमाणु बिजली घर हैं जो 140 टेरावॉट (1 टेरावॉट बराबर 10^{12} वॉट) बिजली का उत्पादन करते हैं, जो वहां निर्मित कुल बिजली का 22.5 प्रतिशत है। ज़ाहिर है यह 140 टेरावॉट बिजली रातोंरात खत्म नहीं हो जाएगी। सात परमाणु बिजली घर तो फुकुशिमा दुर्घटना के तुरंत बाद बंद कर दिए गए थे। इसके पहले एक संयंत्र 2009 में बंद किया गया था। ये आठ संयंत्र कुल 50 टेरावॉट बिजली का उत्पादन करते थे। बाकी के 9 बिजली घर 2022 तक ही चलाए जाएंगे।

सवाल यह है कि फिर जर्मनी अपनी बिजली की ज़रूरतों को पूरा कैसे करेगा? इसका एक समाधान तो तात्कालिक स्तर पर खोजा गया है - मौजूदा कोयला आधारित संयंत्रों की अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करना और फ्रांस तथा अन्य युरोपीय देशों से बिजली का आयात करना। लंबे समय में, जर्मन सरकार चाहती है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का ज़्यादा दोहन किया जाए। फिलहाल जर्मनी की बिजली की कुल ज़रूरत में से 17 प्रतिशत यानी 100 टेरावॉट-घंटे नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होती है। इसे बढ़ाकर 2010 तक 35 प्रतिशत करने की योजना है। इसके अलावा बिजली की खपत में 10 प्रतिशत कमी करना भी एक लक्ष्य है।

यह सवाल भी उठाया जाता है कि यदि आप परमाणु बिजली का सहारा नहीं लेते, तो कार्बन उत्सर्जन पर काबू पाना कठिन है। मगर विशेषज्ञों का मत है कि फिलहाल जर्मनी नवीकरणीय बिजली में प्रति वर्ष 11 टेरावॉट-घंटे का इजाफा कर रहा है। यदि यही दर रही तो उपरोक्त लक्ष्य हासिल करना मुश्किल न होगा। और यदि नवीकरणीय स्रोतों का पर्याप्त दोहन किया गया तो कोयला व गैस आधारित बिजली की ज़रूरत कम हो जाएगी। मगर फिर भी नवीकरणीय स्रोतों से पूरी भरपाई नहीं हो पाएगी, और कोयला व गैस आधारित संयंत्र बनाना होगा।

जर्मनी की योजना यह है कि 2020 में वह अपना कार्बन उत्सर्जन 1990 के स्तर से 40 प्रतिशत नीचे कर ले। एक अनुमान के मुताबिक इसका अर्थ यह है कि 2020 तक उसे अपने कार्बन उत्सर्जन में 7 करोड़ टन प्रति वर्ष की कमी करनी होगी। कई लोग मानते हैं कि परमाणु संयंत्रों के बगैर यह कठिन व महंगा होगा। यदि जर्मनी बाहर से बिजली आयात करेगा तो उन देशों में कार्बन उत्सर्जन बढ़ेगा। युरोप में एक संधि के तहत कार्बन उत्सर्जन के अधिकारों की खरीद-फरोख्त की एक योजना है। जब अन्य देशों में कार्बन उत्सर्जन बढ़ेगा तो वे कहीं न कहीं से इसके अधिकार खरीदेंगे। इसकी वजह से बिजली महंगी हो जाएगी।

मगर इस समय तो जर्मनी में यह दृढ़ निश्चय दिखता है कि 2022 के बाद वहां कोई परमाणु बिजली संयंत्र नहीं होगा। ***(स्रोत फीचर्स)***